संख्या- 21/2020/299(4)/38-6-19-01(एसआरएलएम)/2019

प्रेषक,

राम केशर यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक- 24 सितम्बर, 2020

विषयः- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हेतु वित्तीय वर्ष-2020-21 में अनुदान सं0-81(अनु0जनजाति मद) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश एवं उसके सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पत्रांक-1229/ आजीविका / लेखा/2020-21, दि0-11.08.2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक-जे-17036/57/2013(एसजीएसवाई)-।।(एसपी)पार्ट-1(7सी),दि0-18.06.2020 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत अनुदान सं0-81 (अनु0जनजाति मद) में केन्द्रांश (60 प्रतिशत) रू0 5127.675 लाख (रू0 इक्यावन करोड सत्ताइस लाख सडसठ हजार पॉच सौ मात्र )अवमुक्त की गयी है। अवमुक्त केन्द्रांश (60 प्रतिशत) के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश (40 प्रतिशत) की धनराशि रू0 3418.45 लाख (रू0 चौतीस करोड अट्ठारह लाख पैतालीस हजार मात्र ) बनती है। इस प्रकार अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि रू0 5127.675 लाख एवं इसके सापेक्ष मैचिंग राज्यांश धनराशि रू0 3418.45 लाख सहित कुल धनराशि रू0 8546.125 लाख (रू0 पचासी करोड छियालीस लाख बारह हजार पॉच सौ मात्र ) अवमुक्त किया जाना है। उल्लेखनीय है कि योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-13 के अन्तर्गत रू0 24898.83 लाख बजट की व्यवस्था की गई है। योजनान्र्तगत 60 प्रतिशत केंद्रांश एवं उसके सापेक्ष 40 प्रतिशत राज्यांश (के.60+रा.40) की व्यवस्था है।

2- वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार द्वारा की गई बजट व्यवस्था में उपलब्ध धनराशि में से भारत भारत सरकार के पत्र दि0-18.06.2020 के माध्यम से अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि ) रू0 5127.675 लाख लाख एवं इसके सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की धनराशि रू0 3418.45 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0 8546.125 लाख (रू0 पचासी करोड छियालीस लाख बारह हजार पॉच सौ मात्र ) को अवमुक्त कर आयुक्त, ग्राम्य विकास के निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) आंकडों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न कर, अपितु चरणों में किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(4) धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना विषयक गाइड लाइन/दिशा निर्देश तथा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

(5) स्वीकृत की गयी धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व धनराशि के सदुपयोग का परीक्षण/सत्यापन का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय व स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है, जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को गाइड लाइन में निर्धारित व्यवस्थानुसार समायोजन/व्यय करने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि से यथावश्यकता सामग्री, उपकरण आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

(9) धनराशि के आहरण एवं व्यय के संबंध में मितव्ययिता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) आयुक्त ग्राम्य विकास /मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व मे राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

(11) योजनाओं हेतु प्राविधानित धनराशि को स्वीकृत कर पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं किया जाएगा।

(12) भारत सरकार के पत्र दि0-18.06.2020 में अंकित दिशा-निर्देशों/शर्तों का पूर्णतः अनुपालन किया जाएगा।

(13) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0-1/2020/बी-1-149/दस-2019-231/2019, दि0-24 मार्च, 2020 एवं अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए उसके अनुसार कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-81 के लेखाशीर्षक "2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-796-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जनजातिय उपक्षेत्र योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन(के.60/रा.40-के.+रा.)-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय सं0-यू0ओ0-ई-2-667/दस-19, दिनांक 04-09-2020 में प्राप्त उनकी सहमति तथा समाज कल्याण, बजट प्रकोष्ठ के शासनादेश दि0-27.03.2015 में प्राविधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहे है।

भवदीय,

राम केशर यादव

अनु सचिव।

संख्या-21/2020/ 299(5)/38-6-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय (स्किल डिवीजन), नई दिल्ली।
4- निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य लेखा परीक्षाधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6- मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, गोमती नगर, लखनऊ।
7- अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- ग्राम्य विकास अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राम केशर यादव

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।